

Written by मेरी बटिया संवाददाता
Tuesday, 03 July 2018 21:20

: 0000 0000 00 000000000000 00 000000 00 0000 00 0000 00000000-00000000 00
000000000000 : 0000000000 00 00000 0000 00000000 0000 00 00000 00 00 000000 00
00000000 000000 00 00000 00 00000000 : 000000 0000000000 00 00000 00000 00 0000000000
00000 00 0000000000 0000 00 0000000 0000 0000 00 0000 000000000000 00 00000 00000
00000 :

0000 00000000 000000000000

00 00000000 : अभी उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के.म जोसफ के सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति की फाइल वापस भेजने का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि वेंदर सरकार ने कनया बवाल कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज बनाने के लिये भेजे गये दो नाम मोहम्मद मंसूर और बशारत अली खान के नाम को कानून मंत्रालय ने फिर से वापस कर दिया है। दलील दी गई है कि इन दोनों के खिलाफ कुछ शक्यते हैं।

आपको बता दें कि यह दूसरी बार हुआ है जब इन दोनों के नामों को कानून मंत्रालय ने पुनर्विचार के लिये वापस किया है। इससे पूर्व में भी 2016 में इन दोनों के नाम सरकार ने पुनर्विचार के लिये वापस भेजे थे परंतु सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए इन दोनों नामों की सफिरशि कर दी थी कि दोनों के खिलाफ की गई शक्यते फर्जी हैं। पर सुप्रीम कोर्ट ने लगभग डेढ़ साल तक फाइल को दबाये रखा और अब फिर से दोनों नामों को वापस भेज दिया। कानून के जानकर बताते हैं कि ये कानूनी रूप से गलत है। क्यूंकि अगर किसी नाम की सफिरशि सुप्रीम कोर्ट दुबारा कर देती है तो उस नाम को जज बनाना सरकार के ऊपर बाध्यकारी हो जाता है। परंतु सरकार ने फिर भी दोनों नामों को वापस भेज दिया।

इन दोनों में से ज्यादा चर्चित नाम मोहम्मद मंसूर का है। मंसूर लखनऊ हाईकोर्ट में लगभग बीस सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और सपा सरकार में मुख्य स्थायी अधिवक्ता भी रहे हैं। वे फौजदारी मामलों के जानकर बताये जाते हैं। इनके पिता स्वर्गीय जस्टिस सगीर अहमद सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। कहा जाता है कि वेंदर में कांग्रेस सरकार के दौरान जस्टिस सगीर को कश्मीर के मुद्दे पर बनी ककमटी का अध्यक्ष बनाया गया था। उस ककमटी ने कश्मीर में शांति के लिये कश्मीर को आजादी देने की पैरवी की थी। जब ये रिपोर्ट बाहर आई थी तब इस पर काफी हल्ला भी हुआ था और भाजपा ने खुले तौर पर इस रिपोर्ट का वरीध भी किया था।